भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 94

उत्तर देने की तारीख 1दिसंबर, 2025

सोमवार, 2025/10 अग्रहायण,1947 (शक)

उत्तर प्रदेश में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

94. डॉ. भोला सिंहः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान बुलंदशहर जिले में आईटीआई की संख्या कितनी है, कुल कितने ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं और कितने प्रशिक्षु नामांकित हैं;

(ग) क्या सरकार का बुलंदशहर में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, नए युग के ट्रेड शुरू करने और प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन की समय-सीम क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का कार्यान्वयन करता है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 3,300 आईटीआई (राजकीय- 294 और निजी - 3,006) और 03 एनएसटीआई वर्तमान में सीटीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

(ख): उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में वर्तमान में 41 आईटीआई (राजकीय - 08 और निजी - 33) संचालित किए जा रहे हैं और ये 33 सीटीएस पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान सत्र (वर्ष 2025-26) के दौरान बुलंदशहर जिले के आईटीआई में कुल 4,834 प्रशिक्षुओं को नामांकित किया गया है।

(ग) और (घ): मंत्रिमंडल ने ₹60,000 करोड़ (केंद्रीय हिस्सेदारी: ₹30,000 करोड़, राज्य हिस्सेदारी: ₹20,000 करोड़, और उद्योग हिस्सेदारी: ₹10,000 करोड़) की अनुमानित लागत पर पीएम सेतु (प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए प्रधान मंत्री योजना) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से परिणामोन्मुखीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए हब-एंड-स्पोक व्यवस्था के माध्यम से 1,000 आईटीआई को उन्नत करना है।

इस योजना के अंतर्गत, पाठ्यक्रम सामग्री और डिज़ाइन को उद्योग कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है, और उभरते क्षेत्रों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने और औद्योगिक मूल्यवर्धन को बढ़ाने हेतु भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल सृजित करना है। यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन पर केंद्रित है। मंत्रिमंडल ने वित्तीय-वर्ष 2029-30 तक इस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

*****